

पोरिट्स एंड स्पेंसर (एशिया) लिमिटेड, फरीदाबाद बनाम आयुक्त
आयकर, हरियाणा, रोहतक (जी. सी. मित्तल, जे.)

जी. सी. मित्तल और एस. एस. सोढ़ी जे.जे.

पोरिट्स एंड स्पेंसर (एशिया) लिमिटेड, फरीदाबाद,

बनाम

आयकर आयुक्त, हरियाणा, रोहतक-
उत्तरदाता।

आयकर संदर्भ सं. 1980 के 87 और 88

8 मार्च, 1989।

आयकर अधिनियम (1961 का XLIII) - धारा 33 (1) (ए) और (बी), 33 (1 ए) (बी) 80 जे - पुनर्कंडीशन के लिए सेकंड हैंड प्लांट और मशीनरी का आयात करने वाली असेसी कंपनी - पुरानी मशीनरी के मूल्य का 91 प्रतिशत पुनर्निर्मित करने की लागत - ऐसी पुनर्निर्मित मशीनरी - क्या नई मशीनरी का चरित्र प्राप्त करता है - निर्धारिती - क्या विकास छूट का हकदार है।

यह माना गया है कि यदि रीकंडीशनिंग की लागत सेकंड हैंड मशीनरी की लागत के बराबर या उससे कम है, तो मशीनरी को नया नहीं कहा जा सकता है। जब भी घिसे हुए हिस्सों को फिर से तैयार करने और बदलने की लागत सेकंड हैंड मशीनरी का 5 से 7 गुना होता था, पुनर्निर्मित मशीनरी को नया माना जाता था। यहां मामले के तथ्य नहीं होने के कारण, हम यह मानने के लिए मजबूर हैं कि मशीनरी को नया नहीं माना जा सकता है ताकि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 33 (1) के तहत विकास छूट की मांग की जा सके। चूंकि विचाराधीन आकलन 1. 96 आई.टी.आर. 672

वर्ष धारा 33 में उप-धारा (1ए) को शामिल करने के बाद है, जहां करदाता उपयोग की गई मशीनरी के लिए विकास छूट का हकदार है, इसलिए निर्धारिती को उस प्रावधान के तहत विकास छूट की अनुमति दी जा सकती है और ट्रिब्यूनल उस उप-धारा के तहत उपयोग की गई मशीनरी और संयंत्र के लिए अनुमेय दर पर विकास छूट की अनुमति देने में सही था। (पैरा 18)।

आयकर अपीलीय अधिकरण, चंडीगढ़ बेंच, चंडीगढ़ द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 256(1) के अंतर्गत पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय को आई.टी.ए. में अधिकरण के दिनांक 30 मार्च, 1979 के आदेश से उत्पन्न कानून के निम्नलिखित प्रश्न पर राय लेने के लिए संदर्भित। नहीं। 1976-77 का 847 आर.ए.आकलन वर्ष 1972-73 के लिए 1979 का न्यायाधिकरण का आदेश संख्या 91 और 92:-

(१) क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर, ट्रिब्यूनल ने यह मानकर कानून में गलती की है कि निर्धारिती 1 लाख रुपये की पूंजी पर मूल्यहास का हकदार था। निर्माण, मूल्यहास और विकास छूट की ओर संयंत्र और मशीनरी के लिए 7 लाख रुपये की पूंजी और 2 लाख रुपये पर मूल्यहास और विकास छूट को एक बोक और ऐसे संयंत्र के रूप में माना जाता है।

(२) **चाहे तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर, ट्रिब्यूनल का यह मानना उचित था कि आयकर अधिनियम की धारा 40 ए (5) के तहत अस्वीकृति की गणना करने के**

पोरिट्स एंड स्पेंसर (एशिया) लिमिटेड, फरीदाबाद बनाम आयुक्त
आयकर, हरियाणा, रोहतक (जी. सी. मित्तल, जे.)

**उद्देश्य से, आयकर नियमों के नियम 3 (सी) (ii) के प्रावधानों
को लागू किया जाना चाहिए।**

जी. एल. शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता और मेसर्स अनूप शर्मा और एस.
एस. महाजन, वकील, **अपीलकर्ताओं / याचिकाकर्ताओं के लिए।**

उत्तरदाताओं की ओर से श्री अजय मित्तल, एडवोकेट के साथ वरिष्ठ
अधिवक्ता अशोक भान।

निर्णय

Gokal Chand Mital J.

(1) पोरिट्स एंड स्पेंसर (एशिया) लिमिटेड, निर्धारिती, एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है। करदाता ने व्यापारिक आधार पर बही-खातों का रखरखाव किया और आकलन वर्ष 1972-73 के लिए 23,04,840.00 रुपये के नुकसान की घोषणा करते हुए रिटर्न दाखिल किया, जिसमें 21,44,985.00 रुपये की विकास छूट और आयकर अधिनियम, 1961 (इसके बाद अधिनियम कहा जाता है) की धारा 80 जे के तहत 8,01,872.00 रुपये की कटौती शामिल थी।

(2) करदाता का मामला यह था कि उसने पोरिट्स एंड बीपेंसर लिमिटेड (यूके) से सेकंड हैंड रीकंडीशंड प्लांट और मशीनरी का आयात किया था और कुछ मामलों में सेकंड हैंड प्लांट और मशीनरी के मूल्य के संबंध में रीकंडीशनिंग लागत 80 प्रतिशत से अधिक हो गई थी और मरम्मत करने वालों द्वारा सभी खराब हिस्सों को बदलने के बाद सेकंड हैंड मशीनों को पूरी तरह से गिरा दिया गया था, अलग कर दिया गया था और फिर से बनाया गया था। ये तथ्य पेपर बुक के पृष्ठ 92 पर मुद्रित अनुलग्नक 'जी' में निहित हैं, जिसे करदाता द्वारा आयकर 1. 96 आई.टी.आर. 672

अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। पेपर बुक के पेज 94 पर छपे अनुलग्नक 'एच' में मशीनों और उसके पुर्जों का विवरण, सेकंड हैंड मशीनरी का मूल मूल्य, रीकंडीशनिंग लागत, जिसमें निर्धारिती द्वारा यूके कंपनी को भुगतान किया गया कुल मूल्य शामिल है। सेकंड हैंड प्लांट और मशीनरी का मूल मूल्य £ 60,780 था और रीकंडीशनिंग लागत £ 55,853 के रूप में दिखाई गई है, जो सेकंड हैंड प्लांट और मशीनरी की लागत का 91 प्रतिशत है। भुगतान किया गया कुल मूल्य 50,06,453.00 रुपये था।

(3) 50 लाख रुपये से अधिक की लागत वाले संयंत्र और उर्वरक की उपरोक्त लागत पर, करदाता ने अधिनियम की धारा 33 (1) (ए) के तहत खंड (बी) में निर्दिष्ट दरों पर विकास छूट का दावा किया, जो नई मशीनरी या प्लाम के लिए स्वीकार्य है। वह आयकर अधिकारी ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि मशीनरी और संयंत्र नए नहीं थे और सेकंड हैंड के मूल्य से कम लागत पर विधिवत रूप से पुनर्निर्मित किए गए थे क्योंकि रीकंडीशनिंग और प्रतिस्थापन लागत 91 प्रतिशत थी और इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला गया कि यह एक नई मशीनरी या संयंत्र नहीं था और अधिनियम की धारा 33 (1) (ए) लागू नहीं थी और इसके बजाय धारा 33 (1) लागू की गई थी। ए (बी) जिसके तहत उपयोग की गई मशीनरी या संयंत्र के लिए कम दर पर छूट की अनुमति थी। अतः हमारे समक्ष एक प्रश्न यह होगा कि क्या अधिनियम की धारा 33(1)(क) के अर्थ के अंतर्गत नवीकरण अथवा पुनर्कंडीशन पर सेकंड हैंड मशीनरी और संयंत्र को नया मशीनरी एमडी संयंत्र माना जा सकता है।

(4) करदाता ने पोरिट्स एंड स्पेंसर लिमिटेड, लंकाशायर (यूके) के

पोरिट्स एंड स्पेंसर (एशिया) लिमिटेड, फरीदाबाद *बनाम* आयुक्त
आयकर, हरियाणा, रोहतक (जी. सी. मित्तल, जे.)

साथ एक तकनीकी जानकारी सहयोग समझौता किया था, जिसके तहत निम्नलिखित मदों के तहत दस लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया था -

(एक) भवन खाता : 1,00,000 र

(दो) पौधे और मशीनरी: 7,00,000

(3) पुस्तकें, डिजाइन और सूत्र: 2,00,000

कुल: 10,00,000

(5) करदाता ने दस लाख रुपये की पूरी राशि पर मूल्यहास और संयंत्र, मशीनरी, पुस्तकों, डिजाइन और सूत्रों सहित नौ लाख रुपये की राशि पर विकास छूट का दावा किया। आयकर अधिकारी ने हालांकि गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख किया सी.आई.टी. बनाम *एलेकॉन इंजीनियरिंग* कंपनी लिड। (1), लेकिन मूल्यहास और विकास छूट की राहत को अस्वीकार कर दिया। यह एक और मामला है जिस पर विचार किया जाएगा।

(6) एक और मुद्दा जो निर्धारण के लिए उठता है, वह यह है कि क्या अधिनियम की धारा 40 ए (5) के तहत अस्वीकृति की

गणना के प्रयोजनों के लिए, आयकर नियमों के नियम 3 (सी)
(ii) के प्रावधान को लागू किया जा सकता है?

(7) आयकर अधिकारी के आदेश को अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त टक्स ने बरकरार रखा। आगे की अपील पर, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ ने करदाता को ऊपर दिए गए दूसरे और तीसरे बिंदुओं पर राहत दी, लेकिन पहले बिंदु पर करदाता से सहमत नहीं हुआ। निर्धारिती के कहने पर ट्रिब्यूनल ने उल्लेख किया है! निर्धारिती के कहने पर ट्रिब्यूनल ने राय के लिए निम्नलिखित बिंदु पर विचार किया है: -

“क्या, तथ्यों पर और मामले की परिस्थितियों में, ट्रिब्यूनल ने यह मानकर कानूनन गलती की है कि निर्धारिती उच्चतर विकास छूट का हकदार नहीं था पुनर्निर्मित मशीनरी पर दर रु. 50,06,453?”

(8) राजस्व की सूचना पर निम्नलिखित दो बिन्दुओं को राय के लिए भेजा गया है -

"(i) क्या, तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर, ट्रिब्यूनल ने यह मानकर कानून में गलती की है कि निर्धारिती मूल्यहास का हकदार था! रु. 1 लाख की पूंजी - वार्ड निर्माण, मूल्यहास और विकास छूट रुपये पर. प्लांट जेएनडी मशीनरी और मूल्यहास और विकास छूट के लिए 7 लाख रुपये की पूंजी लगाई गई। 2 लाख को एक किताब और एक पौधे के

पोरिट्स एंड स्पेंसर (एशिया) लिमिटेड, फरीदाबाद बनाम आयुक्त
आयकर, हरियाणा, रोहतक (जी. सी. मित्तल, जे.)

रूप में माना जाता है?

(ii) क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर ट्रिब्यूनल का यह कहना उचित था कि आयकर अधिनियम की धारा 40 ए (5) के तहत अस्वीकृति की गणना के प्रयोजनों के लिए, आयकर नियमों के नियम 3 (सी) (2) के प्रावधानों को लागू किया जाना चाहिए?

(9) हम सबसे पहले करदाता के कहने पर संदर्भित प्रश्न पर विचार करते हैं।

कानूनी डेटा:

(10) 1922 के अधिनियम के तहत, धारा .10 (2) (vi-b) में निहित एक प्रावधान था जो धारा 33 (1) (ए) में निहित प्रावधान के बराबर है। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, यह प्रावधान नई मशीनरी या संयंत्र की बात करता है। 1922 के अधिनियम में प्रयुक्त मशीनरी या संयंत्र प्राप्त करने के लिए विकास छूट की अनुमति देने के लिए कोई समानांतर प्रावधान नहीं था और 1 अप्रैल, 1964 से वित्त अधिनियम 1964 द्वारा अधिनियम में ऐसा प्रावधान जोड़ा गया था।

(11) ऐसा प्रतीत होता है कि धारा 33(1क) को 1 अप्रैल, 1964 से शामिल किए जाने से पहले ही लागू कर दिया गया था। विकास प्रदान करने का मामला

पोरिट्स एंड स्पेंसर (एशिया) लिमिटेड, फरीदाबाद *बनाम* आयुक्त
आयकर, हरियाणा, रोहतक (जी. सी. मित्तल, जे.)

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के समक्ष धारा 33(1)(क) के तहत छूट का उद्देश्य नए स्थापित औद्योगिक उपक्रमों को पुनर्कशकृत मशीनरी अथवा संयंत्र की खरीद पर राहत प्रदान करना था और 1962 के 1962 के परिपत्र संख्या 40 (XLVII-16) के द्वारा सी.बी.आर. से पेपर बुक में अनुलग्नक 'J' के रूप में मुद्रित करके यह निर्णय लिया गया था कि सेकेंड हैंड मशीनरी और संयंत्र जो भारत में विदेश से नए आयात किए गए हैं। धारा 33 के तहत विकास छूट प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए नया माना जा सकता है, जो उसमें उल्लिखित शर्तों के अधीन है। जाहिर है, परिपत्र में निहित निर्णय 1964 के वित्त अधिनियम से पहले लिया गया था, अर्थात्, धारा 33 (आईए) को शामिल करने से पहले, जिसके तहत प्रयुक्त मशीनरी और संयंत्र खरीदने पर भी, विकास छूट की अनुमति दी गई है, लेकिन नई मशीनरी और संयंत्र की खरीद पर स्वीकार्य विकास छूट से कम दर पर।

(12) इस विषय पर पहला निर्णय कोचीन में सर्वोच्च न्यायालय का है / *कंपनी v. सी.आई.टी., केरल* (2). करदाता ने इंग्लैंड से दो वातानुकूलित मशीनों का आयात किया था और प्रारंभिक और अतिरिक्त मूल्यहास का दावा किया था। आगे। आपूर्तिकर्ता ने मशीनों को पूरी तरह से छीन लिया था; पुराने पुर्जों को बदला गया और करदाता को भेजने से पहले नवीनतम संशोधनों को शामिल किया गया और पुनर्निर्मित मशीनों का उपयोग पुनर्संयोजन के समय से लेकर भारत में उनके आगमन की तारीख तक नहीं किया गया था। आयकर अधिकारी और अन्य अपीलीय वैधानिक प्राधिकरणों ने कटौती को अस्वीकार कर दिया था क्योंकि

पोरिट्स एंड स्पेंसर (एशिया) लिमिटेड, फरीदाबाद *बनाम* आयुक्त
आयकर, हरियाणा, रोहतक (जी. सी. मित्तल, जे.)

वे नए नहीं थे। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि रिकॉर्ड पर दिखाई देने वाले एकमात्र तथ्य यह थे कि मशीनों का उपयोग किया गया था, लेकिन आयात से ठीक पहले, खराब भागों के प्रतिस्थापन और नवीनतम संशोधनों को शामिल करने के बाद पूरी तरह से छीन लिया गया था और पुनर्निर्माण किया गया था और निम्नलिखित निर्णय दिया गया था:

"इस अपील में निर्धारण के लिए प्रस्तुत प्रश्न यह है कि क्या अपीलकर्ता द्वारा खरीदी गई दो वातानुकूलित 'जैकस्टोन जूनियर फ्रॉस्टर्स मार्क 2' आयकर अधिनियम की धारा 10 (2) (6) के अर्थ के भीतर नई मशीनें हैं और क्या उस उप-धारा के तहत अपने हैंट +ओ मूल्यहास के हकदार हैं। आयकर अधिनियम में 'नया' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। शॉर्टर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार 'नया' शब्द का अर्थ है 'पहले मौजूद नहीं; अब पहली बार बनाया गया या अस्तित्व में लाया गया। कानून की भाषा के संदर्भ में, विशेष रूप से इसके संदर्भ में

एक मशीनरी पर लागू होने पर, हमारी राय है कि 'नया' शब्द को इस अर्थ में और 'प्रयुक्त' शब्द के विपरीत और विरोध में माना जाना चाहिए। आपूर्तिकर्ताओं के बयान के अनुसार, इस बात पर संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है कि मशीनों का उपयोग पहली बार बनाए जाने के बाद किया गया था। इसके बाद, मशीनों को भागों में ले जाया गया और घिसे हुए कटे हुए हिस्सों को बदलने और नवीनतम संशोधन को शामिल करने के बाद फिर से इकट्ठा किया गया। लेकिन यह सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या दो मशीनें, फिर से वातानुकूलित होने के बाद,

पोरिट्स एंड स्पेंसर (एशिया) लिमिटेड, फरीदाबाद बनाम आयुक्त
आयकर, हरियाणा, रोहतक (जी. सी. मित्तल, जे.)

पुरानी मशीनरी से पूरी तरह से अलग थीं और क्या उनमें शामिल नवीनतम सुधारों ने मशीनों को उप-खंड के अर्थ के भीतर काफी नया बना दिया। दूसरे शब्दों में, सवाल यह है कि क्या इस मामले में दो 'जैकस्टोन जूनियर फ्रॉस्टर्स मार्क द्वितीय' का पुनर्निर्माण या प्रतिस्थापन पूरी मशीनरी का पुनर्निर्माण या प्रतिस्थापन था, जिसका अर्थ है कि पूरी तरह से जरूरी नहीं कि मशीनरी की पूरी विषयवस्तु। इस मामले में उठने वाले कानून के सवाल को इस सिद्धांत की पृष्ठभूमि में परखा जाना चाहिए, लेकिन पक्षों के विद्वान वकीलों को सुनने के बाद, हम संतुष्ट नहीं हैं कि मामले में बयान हमें इसमें उठाए गए कानून के सवाल को तय करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त हैं। उदाहरण के लिए, 1 जुलाई, 1959 के अपने आदेश में, अपीलीय न्यायाधिकरण ने कहा है कि 'वास्तव में हुआ यह था कि एक पूर्ववर्ती तिथि की मशीनों को हटा दिया गया था और नवीनतम उपलब्ध तकनीकी सुधारों को शामिल करते हुए पुनर्निर्माण किया गया था। ट्रिब्यूनल के आदेश में या मामले के बयान में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि वास्तव में 'नवीनतम उपलब्ध तकनीकी सुधार' क्या थे जिन्हें पुनर्निर्मित मशीनों में शामिल किया गया था। यह भी निर्दिष्ट नहीं है कि मशीनों को पहली बार किन तारीखों पर निर्मित किया गया था, किस अवधि के लिए उनका उपयोग पहले किया गया था, मशीनों में शामिल नवीनतम तकनीकी सुधार क्या थे, उनकी प्रकृति और कुल लागत के संबंध में इन सुधारों की प्रकृति और लागत क्या है और इसी तरह। इस सामग्री के अभाव में यह तय करना संभव

पोरिट्स एंड स्पेंसर (एशिया) लिमिटेड, फरीदाबाद **बनाम** आयुक्त
आयकर, हरियाणा, रोहतक (जी. सी. मित्तल, जे.)

नहीं है कि क्या दोनों मशीनें आयकर अधिनियम की धारा 10
(2) (vi-a) के अर्थ के भीतर 'नई' थीं।

(13) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मामले को नए सिरे से तय करने के लिए मामले का पूरक बयान मंगाने के लिए उच्च न्यायालय को वापस भेज दिया गया था। पूर्वोक्त उक्ति के अनुसार निश्चित यह पता लगाने के लिए तथ्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि क्या एक वातानुकूलित मशीनरी को 'नया' कहा जा सकता है और ऐसा करने के लिए, यह देखा जाना चाहिए कि मशीनों का निर्माण पहली बार कब किया गया था; वे पहले किस अवधि के लिए उपयोग किए गए थे; मशीनों में शामिल नवीनतम तकनीकी सुधार क्या थे >; उनकी प्रकृति और कुल लागत आदि के संबंध में इन सुधारों की प्रकृति और लागत क्या है।

(14) अगला मामला **सी.आई.टी., पंजाब बनाम हिंदुस्तान मिल्क फूड मैनुफैक्चरर्स लिमिटेड** (3), इस न्यायालय द्वारा तय किया गया। यहां भी यह पता लगाने के लिए आंकड़े उपलब्ध नहीं थे कि क्या वातानुकूलित मशीनरी को नया माना जा सकता है और मामले का पूरक बयान बुलाया गया था, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने उपरोक्त मामले में किया था। तथ्यों के अनुपूरक विवरण की प्राप्ति पर, इस मामले को इस न्यायालय द्वारा पुन उठाया गया और **सीआईटी, पटियाला बनाम हिंदुस्तान मिल्क फूड मैनुफैक्चरर्स लिमिटेड**(4) मामले में निर्णय दिया गया जहां नवीकरण या पुनर्कडीशनिंग की लागत उपयोग की गई मशीनरी के मूल्य से अधिक नहीं थी, वहां निर्धारिती को राहत नहीं दी

पोरिट्स एंड स्पेंसर (एशिया) लिमिटेड, फरीदाबाद बनाम आयुक्त
आयकर, हरियाणा, रोहतक (जी. सी. मित्तल, जे.)

गई थी, लेकिन जहां भी रीकंडीशनिंग लागत पुरानी मशीनरी की लागत का पांच, छह या सात गुना थी, वहां पुनर्निर्मित मशीनरी को एक नई मशीनरी मानते हुए निर्धारिती को राहत दी गई थी।

(15) उपर्युक्त मामले 1922 अधिनियम के तहत विचार के लिए उत्पन्न होते हैं।

विचार-विमर्श:

(16) जैसा कि इसके पत्र से स्पष्ट है, जिसकी प्रति पेपर बुक में अनुलग्नक 'जी' है, कि उन्होंने सेकंड हैंड रीकंडीशंड प्लांट और मशीनरी खरीदी थी और रिकंडीशन करने से पहले, मशीनों को पूरी तरह से गिरा दिया गया था, छीन लिया गया था और मरम्मत करने वालों द्वारा सभी खराब हिस्सों को बदलने के बाद फिर से बनाया गया था। उनके दस्तावेज से, जिसकी प्रति पेपर बुक में अनुलग्नक 'एच' है, यह स्पष्ट है कि सभी घिसे हुए हिस्सों को फिर से तैयार करने, बदलने आदि की लागत सेकंड हैंड इस्तेमाल की गई मशीनरी और संयंत्र की लागत का 91 प्रतिशत थी। इसका मतलब है कि यदि सेकंड हैंड यूज्ड मशीनरी का मूल्य 100 रुपये था, तो 91 रुपये सभी खराब हिस्सों को फिर से तैयार करने और बदलने में खर्च किए गए थे। करदाता द्वारा कोई अन्य आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किया गया है कि कब

(तीन) 84 आई.टी.आर. 230

(चार) 96 आई.टी.आर. 278.

मशीनों का निर्माण पहले किया गया था; किस अवधि के लिए वे पहले उपयोग किए गए थे और मशीनों में शामिल नवीनतम तकनीकी सुधार, यदि कोई हो, क्या थे। इस डेटा के अभाव में और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सभी घिसे-पिटे पुर्जों को बदलने और रीकंडीशनिंग का काम दूसरे हाथ से इस्तेमाल किए गए संयंत्र और मशीनरी के मूल्य से कम था और *हिंदुस्तान मिल्क फूड मनुजर्स लिमिटेड की आसानी (सुप्रा)* में इस न्यायालय के दूसरे फैसले के आधार पर पुनर्निर्मित मशीनरी को नया नहीं कहा जा सकता है। इस न्यायालय ने उपरोक्त मामले में केवल उन मशीनरी और संयंत्रों को नया माना था जिनमें सभी घिसे हुए भागों के प्रतिस्थापन और पुनः कंडीशनिंग की लागत सेकंड हैंड उपयोग की गई मशीनरी की लागत का 5 से 7 गुना थी और जहां लागत सेकंड हैंड मशीनरी की लागत के बराबर या कम थी, उस मशीनरी या संयंत्र को नया नहीं माना गया था और कटौती की अनुमति नहीं दी गई थी।

(17) उपर्युक्त 3 दिसंबर, 1962 के विभागीय परिपत्र के आधार पर, करदाता के वकील चाहते थे कि हम यह व्यवस्था दें कि कोचीन कंपनी के मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के बावजूद प्रत्येक वातानुकूलित मशीनरी या संयंत्र को एक नई मशीनरी के रूप में माना जाना चाहिए और करदाता द्वारा दावा किए गए प्रावधानों के तहत विकास छूट दी जानी चाहिए। परिपत्र के तहत, धारा 33 के तहत विकास छूट देने के उद्देश्य से पुनर्निर्मित मशीनरी या संयंत्र को नया माना जा सकता है, जैसा कि यह उस समय था, और यह निर्णय कोचीन कंपनी के मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए लिया गया था। 1 अप्रैल, 1964 से नया उपबंध जोड़ा गया और वह नया उपबंध धारा 33(1क) है। इस प्रावधान में प्रयुक्त मशीनरी या संयंत्र की खरीद पर भी कम दर पर विकास छूट प्रदान करने

का प्रावधान है। करदाता के वकील यह तर्क दे सकते हैं कि इस्तेमाल की गई मशीनरी या संयंत्र के लिए धारा 33 (1 ए) लागू होगी और नए और साथ ही पुनर्निर्मित संयंत्र और मशीनरी के लिए, धारा 33 (1) ऊपर उल्लिखित विभागीय परिपत्र के मददेनजर लागू होगी। विद्वान वकील अपनी इस दलील में सही हो सकते हैं, लेकिन फिर से यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के बावजूद हर पुनर्निर्मित या पुनर्निर्मित सेकंड हैंड मशीनरी और संयंत्र को नया माना जाएगा, जिसे विभाग द्वारा जारी परिपत्र के मददेनजर स्वीकार किया गया था। इसलिए, हमें इस मामले के तथ्यों का परिसर में परीक्षण करना होगा कि क्या यह माना जा सकता है कि पुनर्संरचना पर मशीनरी ने एक नई मशीनरी होने का चरित्र हासिल कर लिया है और अधिनियम की धारा 33 (1) के तहत छूट की अनुमति है।

- (18) उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार, चार में से तीन यहां गायब हैं और हमारे पास केवल सेकंड हैंड मशीनरी की लागत और पुनर्कडीशन की लागत है जिसमें सभी घिसे हुए भागों के प्रतिस्थापन की लागत शामिल है, जो 100:91 के अनुपात में है। इस न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए यदि पुनर्कडीशन की लागत सेकंड हैंड मशीनरी की लागत के बराबर या उससे कम है, तो मशीनरी को नया नहीं कहा जा सकता है। जहां कहीं भी पुराने हिस्सों को फिर से तैयार करने और बदलने की लागत सेकंड हैंड मशीनरी की लागत का 5 से 7 गुना थी, वहां पुनर्निर्मित मशीनरी को नई मशीनरी माना जाता था। यहां मामले के तथ्य नहीं होने के कारण, हम इसे मानने के लिए बाध्य हैं। अधिनियम की धारा 33(1) के तहत विकास छूट की मांग करने के लिए मशीनरी को नया नहीं माना जा सकता है। चूंकि विचाराधीन आकलन

वर्ष धारा 33 में उप-धारा (1ए) को शामिल करने के बाद का है, जिसके तहत करदाता उपयोग की गई मशीनरी के लिए विकास छूट का हकदार है, इसलिए निर्धारिती को उस प्रावधान के तहत विकास छूट की अनुमति दी जा सकती है और ट्रिब्यूनल ने उस उप-प्रावधान के तहत उपयोग की गई मशीनरी और संयंत्र के लिए अनुमेय दर पर विकास छूट की अनुमति देना सही था।

हल:

(19) उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम राजस्व के पक्ष में और निर्धारिती के खिलाफ संदर्भित प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में देते हैं और मानते हैं कि ट्रिब्यूनल ने उपयोग की गई मशीनरी और संयंत्र के लिए अनुमेय दरों पर विकास छूट की अनुमति देने में कानून में गलती नहीं की।

राजस्व के उदाहरण पर संदर्भित प्रश्न: प्रश्न 1।

(20) धारा 33 में प्रयुक्त कतिपय शब्द, जिनसे हम संबंधित हैं, और कतिपय अन्य धाराएँ, अधिनियम की धारा 43 में दी गई हैं। उपधारा (3) 'पौधे' को निम्नानुसार परिभाषित करती है: -

"'प्लांट' में जहाज, वाहन, किताबें शामिल हैं। - ■-"

(21) यहां, एक मद 2,00,000 रुपये में पुस्तकों, डिजाइनों और सूत्रों की खरीद है और वे सभी 'प्लांट' के अर्थ के भीतर किताबें हैं और वैज्ञानिक इंजीनियरिंग हाउस प्राइवेट लिमिटेड में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। बहुत। सी.आई.टी., आंध्र प्रदेश (5) ने माना है कि वे सभी 'संयंत्र' का गठन करते हैं और निर्धारिती विकास छूट के साथ-साथ उसी के मूल्य पर मूल्यहास का हकदार है। ट्रिब्यूनल ने करदाता को कटौती की सही अनुमति दी।

- (22) अगला मद संयंत्र और मशीनरी पर तकनीकी जानकारी प्राप्त करने में खर्च किए गए 7,00,000 रुपये हैं। इस मूल्य को संयंत्र और मशीनरी के मूल्य में भी पूंजीकृत किया जाना है और निर्धारिती स्पष्ट रूप से संयंत्र और मशीनरी के मूल्य पर विकास, छूट और मूल्यहास का हकदार है, जिसमें उसी के तकनीकी ज्ञान में खर्च की गई राशि भी शामिल है, और ट्रिब्यूनल टाइल कटौती की अनुमति देने में सही था।
- (23) अगला मद भवन खाते में तकनीकी जानकारी में खर्च की गई 1,00,000 रुपये की राशि है। इस राशि पर, तकनीकी जानकारी की मात्रा को भवन के मूल्य में जोड़ा गया है और कुल मूल्य पर केवल मूल्यहास स्वीकार्य है और इसे ट्रिब्यूनल द्वारा सही अनुमति दी गई है।
- (24) अलग होने से पहले, राजस्व के वकील द्वारा उठाए गए एक तर्क पर ध्यान दिया जा सकता है। उन्होंने उल्लेख किया। 1981 के आई.टी.रेफ नंबर 90 में हमारा निर्णय, सी.एल.टी. **सुपर स्टील्स** (0) ने 1 मार्च, 1989 को तकनीकी जानकारी पर खर्च की गई राशि पर राहत देने से इनकार कर दिया। उपरोक्त मामले में करदाता ने दावा किया था कि राजस्व व्यय के रूप में तकनीकी जानकारी पर खर्च की गई राशि और उसे इसकी अनुमति दी गई थी। राजस्व के विद्वान वकील यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं कि तकनीकी जानकारी प्राप्त करने में खर्च की गई राशि राजस्व व्यय होगी और उनके अनुसार यह पूंजीगत प्रकृति की होगी और फिर भी वह चाहते हैं कि करदाता को राहत देने से इनकार किया जाना चाहिए।
- (25) राजस्व व्यय के रूप में दावा करने के लिए, 10,00,000 रुपये की पूरी राशि को बाहर कर दिया जाएगा; जबकि करदाता यह चाहता है कि राशि को पूंजी खाते में जोड़ा जाए और उसे पहले

दो मर्दों पर विकास छूट और मूल्यहास की अनुमति दी जाए, और तीसरे आइटम पर मूल्यहास की अनुमति दी जाए। ऊपर उल्लिखित सुप्रीम कोर्ट के मामले में, करदाता ने राजस्व व्यय के रूप में कटौती का दावा नहीं किया था, और पूंजीगत प्रकृति की तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के लिए किए गए खर्चों पर विचार किया था और मूल्यहास का दावा किया था और इसकी अनुमति दी गई थी। इस मामले में भी करदाता ने तकनीकी जानकारी प्राप्त करने में खर्च की गई राशि का दावा किया है और कटौती का दावा किया है। जैसा कि पहले ही कहा है की दावा राजस्व व्यय करदाता के लिए अधिक फायदेमंद होता, लेकिन यदि वह इस आधार पर कम लाभ लेना चाहता है कि यह पूंजीगत व्यय की प्रकृति में था, तो कटौती को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है और राजस्व की ओर से उठाए गए तर्क को खारिज कर दिया जाता है,

(26) ऊपर दर्ज कारणों के लिए, हम इस प्रश्न का उत्तर निर्धारिती के पक्ष में, नकारात्मक में देते हैं।

प्रश्न 2.

(27) यह मामला हमारे निर्णय में *सी.एल.टी. न्यूकेम प्लास्टिक्स लिमिटेड* (7) 2 फरवरी, 1989 को निर्धारिती के पक्ष में दिया गया। हमने कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय का अनुसरण किया था। *ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड* (8) इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कि अधिनियम की धारा 40 ए (5) के तहत असंगति की गणना करते समय, आयकर नियमों के नियम 8 (सी) (ii) के प्रावधानों को लागू किया जाना चाहिए। गुजरात उच्च न्यायालय ने आज *सी.एल.टी. मामले में एक नया फैसला सुनाया* बहुत। *राजेश टेक्सटल मिल्स लिमिटेड* (9) राजस्व के वकील द्वारा विपरीत दृष्टिकोण अपनाने का हवाला

दिया गया है। मामले पर विचार करने पर, हम पहले दर्ज किए गए अपने दृष्टिकोण का पालन करना पसंद करते हैं और करदाता के पक्ष में इस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक में देते हैं।

संदर्भों का निपटान लागत के बारे में बिना किसी आदेश के किया जाता है।

पी.सी.जी.

ए. पी. चौधरी जे. के समक्ष

शाम कुमार मोदगिल, - अपीलकर्ता।

बनाम

भारतीय स्टेट बैंक और अन्य, *उत्तरदाता।*

नियमित द्वितीय अपील सं.20 अप्रैल, 1989 को 330 ऑफ 1986।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 - धारा 10 - अनुशासनात्मक कार्रवाई - ट्रायल कोर्ट द्वारा नैतिक अधमता को कम करने वाले अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया कर्मचारी, हालांकि, परिवीक्षा पर रिहा कर दिया गया - बैंक एस के संदर्भ में कर्मचारी को बर्खास्त कर देता है। 10 को वारा 521 के साथ पढ़ा जाता है **जिसमें निर्दिष्ट अपराधों के लिए दोषसिद्धि पर बर्खास्तगी का प्रावधान है - बर्खास्तगी का आदेश उस आचरण पर आधारित होना चाहिए जिसके कारण दोषसिद्धि हुई न कि इसके लिए।**

(सात) 1983 के आई.टी.बी. का निर्णय 2 फरवरी, 1989 को हुआ

(आठ) 135 आई.टी.आर. 35

(नौ) 173 आई.टी.आर. 179

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी

व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मयंक गुप्ता
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
चरखी दादरी, हरियाणा